JAGRAN Josh

Simplifying Test Prep

WWW.JAGRANJOSH.COM

करेंट अफेयर्स अगस्त 2013

विषय-सूची

विषय-सूची 2

प्रस्तावना 16

अंतरराष्ट्रीय | विश्व 17

भूटान को 5000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने पर भारत सहमत 17

आसियान रक्षा मंत्रियों की द्वितीय बैठक (प्लस) में संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया 17

भारत – कनाडा सामाजिक सुरक्षा समझौते को कैबिनेट ने मंजूरी दी 18

ब्रिटेन की संसद में सीरिया सरकार के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई का प्रस्ताव नामंजूर 19

ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन पर भारत और इराक के मध्य हस्ताक्षर 19

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण समर्थन परियोजना प्रारंभ 21

पांचवी भारत-चीन सामरिक वार्ता नई दिल्ली में संपन्न 22

आवास वित्त परियोजना हेतु विश्वबैंक से 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर 23

इजराइल ने फिलिस्तीन के साथ शांतिवार्ता से पहले 26 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया 23

भारत और एडीबी के बीच बिहार में 254 किमी राजमार्गों के उन्नयन हेतु समझौता 24

इजराइल ने 26 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई को मंजूरी दी 24

भारत ने मोरक्को के साथ दोहरे कराधान परिहार समझौते पर हस्ताक्षर किए 25

उत्तर और दक्षिण कोरिया केसोंग औद्योगिक क्षेत्र को पुनः खोलने हेतु बातचीत के लिए सहमत 25

अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास पर आत्मघाती हमले के पीड़ितों हेतु सहायता की घोषणा 26

'द वांशिगटन पोस्ट' दैनिक अखबार को अमेरिका के पोर्टल अमेजन के सीईओ ने खरीदा 26

अमेरिका की विश्वविख्यात साप्ताहिक पत्रिका को आईबीटी मीडिया ने खरीदा 27

जिंबाब्वे संसदीय चुनाव-2013: रॉबर्ट मुगाबे 7वें कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित 28

अयोग्यता के खिलाफ जमात-ए-इस्लामी पार्टी की याचिका खारिज 29

ऑस्ट्रेलिया में आम चुनाव 7 सितम्बर 2013 को कराने का निर्णय 29

आईआईटी हैदराबाद और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की सहयोग परियोजना को मंजूरी 30

ढाका के उच्च न्यायालय ने बांग्लादेश की जमात-ए-इस्लामी को अवैध घोषित किया 30

विश्व डायरी 32

राष्ट्रीय | भारत 40

सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों व्याख्या की 40

कंपनी विधेयक-2013 को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने मंजूरी दी 40

लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक 2013 41

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन विधेयक 2012.....42

कार्मिक, लोकशिकायत, विधि तथा न्याय संबंधी संसद की स्थायी समिति की 61वीं रिपोर्ट 43

विवाह विधि (संशोधन) विधेयक-2010 44

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक-2013 45

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन को मंजूरी दी 47

प्रधानमंत्री और यूपीए अध्यक्ष ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र का नई दिल्ली में शुभारंभ किया.....47

सार्वजनिक-निजी साझेदारी के तहत पांच नये आईआईआईटी शैक्षिक सत्र 2013-14 से शुरू.....48

न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित करने का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर 49

सरकार ने मधुमेह रोधक औषधि प्योग्लिटाजोन पर लगी रोक सशर्त हटाई.....49

सभी केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों से सूचना पाने हेतु ऑनलाइन आवेदन सुविधा की शुरुआत 51

दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की शुरूआत 51

सरकार ने नागरिकता कानून में बदलाव का फैसला किया.....52

राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक 2013 का मसौदा तैयार 53

विश्वविद्यालय से संबद्ध होने वाले कॉलेजों की अधिकतम संख्या 200 तक सीमित 54

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक 2012.....55

धारवाड़ और गुलबर्ग में कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थायी खंड पीठ की स्थापना के आदेश 56

प्रस्तावना

करेंट अफेयर्स ई-बुक (eBook) अगस्त-2013 विभिन्न प्रतियोगी व प्रवेश परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी अध्ययन सामग्री है जो कि विभिन्न क्षेत्रों की परीक्षोपयोगी घटनाओं का वृहद संकलन है.

करेंट अफेयर्स ई-बुक (eBook) अगस्त-2013 में प्रस्तुत घटनाओं का तथ्यपरक विवेचन व विश्लेषण भी किया गया है. यही नहीं, करेंट अफेयर्स पर प्रस्तुत ई-बुक में घटनाओं की पृष्ठिभूमि का भी वर्णन किया गया है.

करेंट अफेयर्स ई-बुक (eBook) अगस्त-2013 में भारत और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों यथा-राजनैतिक, आर्थिक, कार्पोरेट वैज्ञानिक, तकनीक, पारिस्थितीकी, खेल, अंतरिक्ष, पर्यावरणीय, पुरस्कार, चिकित्सकीय एवं साहित्य, आयोग, आदि समेत उन सभी घटनाओं को समाहित किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं. यह समस्त पाठ्य सामग्री www.jagranjosh.com के विशेषज्ञों द्वारा अगस्त- 2013 माह के करेंट अफेयर्स पर तैयार की गई है.

राजस्थान तथा झारखंड राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए परीक्षाओं के लिए करेंट अफेयर्स ई-बुक (eBook) अगस्त-2013 अत्यंत महत्त्वपूर्ण है जो कि परीक्षार्थियों की करेंट अफेयर्स संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है.

करेंट अफेयर्स ई-बुक (eBook) अगस्त-2013 सिविल सेवाओं (IAS\PCS), बैंकिंग, SSC, UGC, NET, TET के लिए उपयोगी हैं.

अंतरराष्ट्रीय | विश्व

भूटान को 5000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने पर भारत सहमत

भूटान के सामाजिक-आर्थिक विकास में सहयोग के अपने वादे पर आगे बढ़ते हुए भारत ने पड़ोसी देश भूटान को 5000 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने 31 अगस्त 2013 को घोषणा की. इस राशि में 500 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज भी शामिल है. यह घोषणा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे के बीच हुई बैठक की गई. भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे 30 जुलाई 2013 से 6 दिन की भारत की राजकीय यात्रा पर हैं. भूटान का प्रधानमंत्री बनने के बाद शेरिंग तोबगे की भारत की पहली राजकीय यात्रा है. शेरिंग तोबगे जुलाई 2013 में भूटान के प्रधानमंत्री बने थे.

दोनों देशों द्वारा जारी साझा बयान के मुख्य बिदु

दोनों देशों की ओर से जारी साझा बयान में कहा गया कि भारत और भूटान द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में प्रयासरत रहेंगे.भारत ने भूटान को 11वीं पंचवर्षीय योजना (1 जुलाई 2013 से 30 जून 2018) में विकास कार्यो के लिए यह सहायता राशि प्रदान की है. बयान में कहा गया कि भूटान के आग्रह पर 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारत 4,500 करोड़ रुपये देगा. इसके अतिरिक्त 500 करोड़ रुपये आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के रूप में दिए जाएंगे. भूटान में चल रही तीन विद्युत परियोजनाओं पर संतुष्टि जताते हुए भारत ने 10 हजार मेगावाट के एक नए प्लांट के निर्माण के प्रति एक बार फिर प्रतिबद्धता जताई.

विश्लेषण

भारत का यह कदम ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच रिश्तों की प्रगाढ़ता में कमी को देखने को मिली थी.

विदित हो कि गत दिनों भारत ने भूटान को सब्सिडी वाला ईंधन देने से मना कर दिया था. यद्यपि बाद में भारत ने अपना यह फैसला वापस ले लिया था.

आसियान रक्षा मंत्रियों की द्वितीय बैठक (प्लस) में संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया

विश्व डायरी

1 अगस्त 2013

• अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति ने वर्ष 2016 के रियो दी जेनेरियो (ब्राजील) ओलंपिक खेलों सहित कई खेल कार्यक्रमों का प्रसारण अधिकार सात एशियाई देशों के लिए भारतीय चैनल स्टार इंडिया को दिया.

• विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बालकोष की ओर से विश्व स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया गया.

• बांग्लादेश के ढाका उच्च न्यायालय ने देश की राजनीतिक पार्टी जमात-ए-इस्लामी (Jamaat-e-Islami) को 'अवैध' घोषित करते हुए भविष्य में उसके चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया.

2 अगस्त 2013

• अमेरिका के तैराक रेयान लोश्टे ने विश्व तैराकी चैंपियनशिप-2013 में 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले का स्वर्ण पदक जीता.

• रूना लैला, एचआईवी/एड्स के लिए दक्षेस सद्भावना राजदूत की भारत यात्रा सम्पन्न हुई.

• भारतीय जूनियर तीरंदाजी कंपाउंड पुरुष टीम ने एशियाई ग्रां प्री तीरंदाजी प्रतियोगिता-2013 में स्वर्ण जीता.

3 अगस्त 2013

• जिंबाब्वे संसदीय चुनाव-2013: रॉबर्ट मुगाबे 7वें कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित.

• भारत ने जिम्बाब्वे को सात विकेट से पराजित कर पांच एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का पांचवां एवं अंतिम मैच जीता.

• पत्रकारिता के क्षेत्र में समूचे विश्वस्तर में विख्यात अमेरिका की साप्ताहिक पत्रिका न्यूजवीक को अमेरिका के ही एक प्रमुख मीडिया समूह आईबीटी मीडिया ने खरीदा.

4 अगस्त 2013

• ईरान में हसन रूहानी ने तेहरान स्थित संसद 'मिल्ली मजलीस' में आयोजित एक समारोह में देश के राष्ट्रपति के पद की शपथ ली.

• भारत ने सुशीला चानू की कप्तानी में जूनियर महिला हॉकी विश्व कप-2013 में इंग्लैंड को 3-2 से पराजित कर कांस्य पदक जीता.

• जापान ने विश्व के पहले बोलने वाले रोबोट 'किरोबो' को अंतरिक्ष में भेजा.

5 अगस्त 2013

• चीन के शहर ग्वांगझू में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप-2013 का प्रारम्भ हुआ.

• बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने वाली जमात-ए-इस्लामी पार्टी की याचिका खारिज कर दी.

• सर्वोच्च न्यायालय ने अबू सलेम की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अबू सलेम ने पुर्तगाल की अदालत द्वारा प्रत्यर्पण को रद्द किए जाने के बाद यहां अपने खिलाफ चल रही सभी कानूनी प्रक्रियाओं को खत्म करने की मांग की थी.

6 अगस्त 2013

• अमेरिका की पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची में रूस की मारिया शारापोवा शीर्ष स्थान पर.

• माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑफिस 365 को लॉन्च किया.

7 अगस्त 2013

• उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया केसोंग औद्योगिक क्षेत्र को फिर से खोलने के लिए बातचीत करने को राजी हो गए.

• भारत ने अफगानिस्तान के जलालाबाद में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हुए आत्मघाती हमले में मारे गए निर्दोष अफगान लोगों के लिए डेढ़ लाख डालर की सहायता की घोषणा की.

• उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा ब्रिटेन के कहानीकार तेजेन्द्र शर्मा का चयन वर्ष 2012 के प्रवासी भारतीय हिन्दी भूषण सम्मान के लिए किया गया.

8 अगस्त 2013

राष्ट्रीय | भारत

सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों व्याख्या की

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय और न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की खंडपीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायलय के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि दुकान या रिहायश खाली करने को लेकर मकान मालिक और किराएदार के विवाद में अगर प्रतिवादी समन तामील होने के 90 दिन के अंदर अपना पक्ष अदालत में पेश नहीं करता तो ट्रायल कोर्ट उसके जवाब को खारिज कर सकता है. सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के तहत 90 दिन की सीमा अनिवार्य है. खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि प्रतिवादी से जुर्माना वसूल करके उसके जवाब को स्वीकार नहीं किया जा सकता. न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय और न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की खंडपीठ ने सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायलय के फैसले को पलट दिया. खंडपीठ ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने अमरोहा की निचली अदालत के दोनों फैसलों के विपरीत निर्णय देकर गलती की. इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का हवाला देकर निचली अदालत के फैसलों को खारिज दिया लेकिन शीर्ष अदालत के आदेश को उद्धृत नहीं किया. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को उद्धृत किए बिना इस तरह निचली अदालत के निर्णय को खारिज करना उचित नहीं है.

सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 90 दिन की निर्धारित सीमा के अंदर जवाब दायर नहीं करने के कारण प्रतिवादी के पक्ष को नकारने के ट्रायल कोर्ट और जिला न्यायाधीश के निर्णय को सही ठहराया. सर्वोच्च न्यायालय खंडपीठ ने मकान मालिक की 2007 में दायर विशेष अनुमति याचिका का निपटारा करते हुए ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि 1998 में दायर मामले का जल्द फैसला किया जाए.

विवाद

अमरोहा के बाल गोपाल माहेश्वरी ने अपनी दुकान को खाली कराने के लिए अपने किराएदार संजीव कुमार गुप्ता के खिलाफ दीवानी अदालत में सितम्बर 1998 में दावा दायर किया था. प्रतिवादी संजीव कुमार गुप्ता को अदालत ने नोटिस जारी किया. नोटिस तामील भी हुआ लेकिन किराएदर ने 90 दिन की अनिवार्य अवधि में जवाब दायर नहीं किया. 90 दिन की निर्धारित अवधि के बाद दायर जवाब को अदालत ने अस्वीकार कर दिया.

कंपनी विधेयक- 2013 को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने मंजूरी दी

कंपनी विधेयक-2013 को 29 अगस्त 2013 को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने मंजूरी प्रदान की. इस नए कंपनी कानून के अस्तिस्त में आने के बाद देश में उद्योगों के लिए बनाया गया करीब छह दशक पुराना कानून निष्प्रभावी हो जाना है. कंपनी विधेयक-2013 द्वारा कंपनी कानून 1956 का स्थान लिया जाना है. कंपनी मामलों का मंत्रालय फिलहाल इस विधेयक के नए नियम एवं कानून तैयार कर रहा है. कानून के तहत नए कायदा कानूनों का मसौदा दो सप्ताह में सुनिश्चित हो जाने की उम्मीद है.

विदित हो कि राज्यसभा ने 8 अगस्त 2013 को कंपनी विधेयक-2012 को ध्वनिमत से पारित किया था. लोकसभा ने इस विधेयक को दिसंबर-2012 में ही मंजूरी प्रदान की थी.

लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक 2013

लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक, 2013 को राज्यसभा में 30 अगस्त 2013 को पेश किया गया. कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने इस विधेयक को पेश किया. इसके जरिये वर्ष 1951 के मूल कानून में बदलाव किए जाने हैं. यदि यह विधेयक संसद से पारित होने के बाद कानून बन गया तो यह 10 जुलाई 2013 से लागू होना है. उसी दिन सर्वोच्च न्यायालय ने दो निर्णय दिए थे. इनके तहत दोषी साबित किए गए सांसदों एवं विधायकों की सदस्यता को समाप्त करने तथा ऐसे लोगों के जेल से चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई.

लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक , 2013 का उद्देश्य

इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय के दो फैसलों को निष्प्रभावी बनाने है जिसमें दोषी ठहराये गए सांसदों एवं विधायकों को फौरन अयोग्य घोषित करने और उनके चुनाव लड़ने पर रोक संबंधित व्यवस्था दी गई थी.

विधेयक पर केंद्र सरकार का मत

विधेयक के कारणों एवं उद्देश्यों में कहा गया कि सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश की समीक्षा की है तथा भारत के एटार्नी जनरल से विचार विमर्श कर इस आदेश के खिलाफ पुनरीक्षा याचिका दायर की है. इसमें कहा गया कि इसके अतिरिक्त सरकार का यह मत है कि उक्त पुनरीक्षा याचिका के निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से पैदा हुई स्थिति से उपयुक्त रूप से निबटने की जरूरत है. अत: उक्त कानून का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया.

लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक , 2013 के मुख्य बिंदु

इसमें प्रस्तावित है कि विधायक या विधान पार्षद को तब अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है जबकि वह दोषी साबित होने के 90 दिनों के भीतर अपील दाखिल कर देता है या फैसले पर स्थगन आदेश मिल

जाता है. जन प्रतिनिधि कानून में संशोधन के लिए लाए गए इस विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि दोषी ठहराये जाने के बाद कोई सांसद या विधायक को अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता बशर्ते कि उनकी अपील अदालत के सामने लंबित हो और फैसले पर स्थगनादेश दिया गया हो.

भूमि अधिग्रहण , पुनर्वास और पुनर्स्थापन विधेयक 2012

उचित मुआवज़ा और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में पारदर्शिता का अधिकार विधेयक, 2012 को लोकसभा में कुछ संशोधनों के साथ 29 अगस्त 2013 को पारित किया गया. ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने विधेयक लोकसभा में पेश किया. विधेयक के पक्ष में 216 जबकि विपक्ष में 19 सांसदों ने वोट डाले. विधेयक में 381 संशोधन पेश किए गए जिसमें से 166 आधिकारिक रूप से दर्ज किए गए. विपक्ष द्वारा दिए गए संशोधनों में से कुछ वापस ले लिए गए और कुछ मतदान के दौरान गिर गए. अब इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया जाना है.

विधेयक का उद्देश्य

इसका उद्देश्य भूमि अधिग्रहण हेतु नए नियम और मुआवज़ा नीति निर्धारित करना है. वर्तमान देश में जमीन अधिग्रहण वर्ष 1894 में बने कानून के तहत होता है. मौजूदा वक्त के हिसाब से इस कानून में कई कमियां हैं. इसमें जमीन के अधिग्रहण के बाद प्रभावितों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है.

विधेयक के मुख्य बिंदु

विधेयक के प्रावधानों के तहत किसानों की शिकायतों के निपटारे के लिए एक भूमि अपील प्राधिकरण का गठन किए जाने का प्रस्ताव है. इसमें जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है और उन्हें पर्याप्त हर्जाना नहीं मिला है, ऐसे किसान अपनी शिकायतों का निपटारा करा सकेंगे. यदि किसान अपील प्राधिकरण के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो उन्हें उच्च न्यायालय जाने का भी अधिकार होना है. इसमें बहुफसल खेती वाली जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाना है और यदि इसकी आवश्यकता भी हुई तो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में निर्णय लिया जाना है. विधेयक में बहुफसली और सिंचित जमीन के अधिग्रहण के बारे में विशेष प्रावधान हैं.

• विधेयक में उचित हर्जाना और पारदर्शिता के अधिकार के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के वास्ते भूमि अधिग्रहण हेतु 70 प्रतिशत जबकि निजी कंपनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए 80 प्रतिशत सहमति लेना आवश्यक होना है.

• विधेयक में किसानों के लिए उचित और न्यायसंगत हर्जाना देने और कोई भी जमीन बलपूर्वक अधिग्रहित नहीं किए जाने का प्रस्ताव है.

• प्रस्तावित हर्जाने में ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य का चार गुना जबकि शहरी क्षेत्रों में बाजार मूल्य के दोगुने तक का हर्जाना दिए जाने का प्रस्ताव है

• प्रस्तावित हर्जाने में ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य का चार गुना जबकि शहरी क्षेत्रों में बाजार मूल्य के दोगुने तक का हर्जाना दिए जाने का प्रस्ताव है.

• इस कानून में अधिग्रहण के कारण जीविका खोने वालों को 12 महीने के लिए प्रति परिवार तीन हज़ार रुपये प्रति माह जीवन निर्वाह भत्ता दिए जाने का प्रावधान है.

• पचास हजार का पुनर्स्थापना भत्ता, प्रभावित परिवार को ग्रामीण क्षेत्र में 150 वर्ग मीटर में मकान, शहरी क्षेत्रों में 50 वर्गमीटर ज़मीन पर बना बनाया मकान दिए जाने का प्रावधान भी इस कानून में किया गया.

कार्मिक, लोकशिकायत , विधि तथा न्याय संबंधी संसद की स्थायी समिति की 61वीं रिपोर्ट

कार्मिक, लोकशिकायत, विधि तथा न्याय संबंधी संसद की स्थायी समिति ने अपनी 61वीं रिपोर्ट संसद में 26 अगस्त 2013 को पेश की. इस रिपोर्ट में चुनाव सुधारों के संबंध में यह सिफारिश की गई है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता को चुनाव की घोषणा की तारीख के बजाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू किया जाना चाहिए. समिति ने उम्मीदवार की चुनाव खर्च सीमा को अधिक वास्तविक बनाने के लिए इसमें सुधार तथा चुनाव संबंधी विवादों का 12 महीने में निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करने की भी अनुशंसा की है. कार्मिक, सार्वजनिक शिकायत, विधि व न्याय संबंधी संसदीय समिति ने 'चुनाव सुधार-राजनीतिक दलों की आचार संहिता तथा दलबदल कानून' विषय पर संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में आयोग की सीमा रेखा तय करने की वकालत की है. समिति ने संविधान के अनुच्छेद 324 में उल्लिखित चुनाव आयोग के अधिकारों की सीमा दिखाई है. इसके तहत चुनाव आचार संहिता को कानून के जरिए संवैधानिक आधार देने की वकालत की गई है, ताकि चुनाव आयोग अधिकारों का गलत उपयोग न कर पाए.

समिति ने किसी राजनीतिक दल की मान्यता रद्द करने संबंधी निर्वाचन आयोग की शक्तियों के संबंध में रिपोर्ट में कहा है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 क के अनुसार निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों को पंजीकृत करने की शक्ति प्रदान की गयी है किंतु उसे किसी राजनीतिक दल के पंजीकरण को रद्द करने की शक्ति प्रदान नहीं की गयी है. लेकिन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन होने की स्थिति में किसी राजनीतिक दल की मान्यता रद्द करने के लिए निर्वाचन प्रतीक नियम

भारत डायरी

1 अगस्त 2013

• भारत का मौसम संबंधी उन्नत उपग्रह, इनसेट-3डी सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हुआ.

• राष्ट्रपति भवन पर्यटन की ऑनलाइन बुकिंग के लिए ई-भुगतान सुविधा की शुरूआत राष्ट्रपति की सचिव ओमिता पॉल ने की.

• मेट्रो मैन ई श्रीधरन को वर्ष 2013 के लोकमान्य तिलक पुरस्कार से पुणे में सम्मानित किया गया.

2 अगस्त 2013

• केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष के गठन को मंजूरी दी.

• मलयालम भाषा की कवयित्री और सामाजिक कार्यकर्ता सुगाथा कुमारी को काव्य संग्रह मनलेक्षुतु (Manalezhuthu) के लिए वर्ष 2012 के सरस्वती सम्मान (22वां) से सम्मानित किया गया.

• मलयालम भाषा के साहित्यकार प्रो. ए अरविंदाक्षन को हिंदी भवन न्यास समिति, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2013 के हिंदी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया.

3 अगस्त 2013

• केंद्र सरकार ने अरुंधती भट्टाचार्य को भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया.

• आस्कर फर्नांडिस ने एनएच-37 पर 2 लेन का फ्लाई ओवर राष्ट्र को समर्पित किया.

4 अगस्त 2013

• पूर्व अंतरराष्ट्रीय अंपायर देशराज का पुणे में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया.

• झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छह मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया.

• सैन्य मामलों के रणनीतिक चिंतक एयर कोमोडोर (सेवानिवृत्त) जसजीत सिंह का नई दिल्ली में निधन हो गया.

5 अगस्त 2013

• राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने देश भर में बगैर लाइसेंस और पर्यावरण मंजूरी के बिना नदियों के किनारे और तली से रेत निकालने और खनन पर प्रतिबंध लगा दिया.

• सर्वोच्च न्यायालय ने नोएडा के सलारपुर गांव में आपात उपबंध के तहत 182 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को लेकर जारी अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया.

• उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने आपदा प्रबंधन के लिए दो समितियां बनाने और एक विशेषीकृत राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल गठित करने की मंजूरी प्रदान की.

6 अगस्त 2013

• पहले हंस कथा सम्मान (वर्ष 2012-13) के लिए कथाकार किरण सिंह का चयन किया गया.

• भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर रघुराम गोबिंद राजन को तीन वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त करने का निर्णय लिया.

• पटना उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में बिहार राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली प्रारंभिक जांच परीक्षा (पीटी) में आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया.

7 अगस्त 2013

• केंद्रीय संस्कृति मंत्री चंद्रेश कुमारी कटोच ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में युवा दर्शक कार्यक्रम 'युवा साथी' शुरू किया.

• महाराष्ट्र, आधार से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से राज्य सरकार के कर्मचारियों को वेतन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया.

• उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान ने वर्ष 2012 के पुरस्कारों की घोषणा लखनऊ में की.

8 अगस्त 2013

अर्थव्यवस्था

वरिष्ठ उम्र के निवेशकों हेतु कर योग्य बचत बांडों पर अवधि से पूर्व 8% भुगतान की अनुमति

भारतीय रिजर्व बैंक ने कर योग्य बचत बांडों की अवधि पूरी होने से पूर्व साठ वर्ष या अधिक उम्र के निवेशकों को आठ फीसदी भुगतान की अनुमति 30 अगस्त 2013 को दी. हालांकि रिजर्व बैंक ने अवधि से पूर्व भुगतान के लिए कम से कम तीन वर्षों की समय सीमा तीन वर्ष निश्चित की. इस प्रकार वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी वाले निवेशकों को कर योग्य बचत बांडों में निवेश के लिए पूर्व भुगतान के लिए राशि की सीमा आठ फीसदी तथा कम से कम तीन वर्षों के बाद भुगतान किये जाने की समय सीमा निर्धारित की. हालांकि संयुक्त बॉण्ड धारकों के मामले में किसी एक व्यक्ति को निर्धारित शर्त पूरी करनी होगी. इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक ने नगरीय इलाकों में स्थित सहकारी बैंकों को निर्देश जारी किये हैं कि वे ऐसे न्यासों व संस्थाओं को दान देना बंद करें, जिनमें उनके निदेशक या उनके रिश्तेदार किसी पद पर हों या उनके हित हों. वर्तमान में, इन बैंकों को पिछले वर्ष के लाभ का एक प्रतिशत हिस्सा ट्रस्टों और संस्थाओं को दान के रूप में देने की अनुमति है.

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया-द वे फॉरवर्ड नामक चर्चा पत्र जारी किया

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया-द वे फॉरवर्ड नामक चर्चा पत्र को 27 अगस्त 2013 को जारी किया. चर्चा पत्र में बैंकिंग संरचना के पुनरभिविन्यास से संबंधित कई विषयों पर चर्चा की गई, इनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उच्च विकास के वित्तपोषण, विशेष सेवाएं प्रदान करने और वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना शामिल है. चर्चा पत्र में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए व्यापार बंद के प्रबंधन हेतु बदलाव से उत्पन्न चिंताओं को दूर करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया. आरबीआई ने 'बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया- द वे फॉरवर्ड' पेपर में कहा, बैंकिंग के फाइनेंशियल इनक्लूजन के मकसद और भौगोलिक पहुंच तभी बढ़ सकती है, जब एंट्री प्रोसेस पाबंदी लगाने वाली न हो.

पेपर में भारत में नए बैंक खोलने हेतु लगातार विचार को सही माना गया, जबकि मौजूदा व्यवस्था यह है कि नए बैंकों खोलने की प्रक्रिया अलग-अलग अंतराल में शुरू की जाती है. आरबीआई ने लाइसेंसिंग पॉलिसी को तीन से 5 वर्ष की शेल्फ लाइफ के साथ सही माना है.

बैंकिंग व्यवस्था इन इंडिया-द वे फॉरवर्ड, चर्चा पत्र के मुख्य बिंदु

• पत्र में केंद्रीय बैंक ने कहा,'बैंकिंग सेक्टर की गुणवत्ता सुधारने और प्रतिस्पद्रधा को बढ़ावा देने के लिए यह जरूरी है कि नए बैंकों के प्रवेश के लिए नियम सख्त किए जाएं जिससे कि बेहतर इकाइयां ही आवेदन कर सकें.

• घरेलू बैंकों के लिए 4- टीयर व्यवस्था का सुझाव देते हुए नए बैंकों के प्रवेश के नियम सख्त करने की बात कही.

• प्रस्तावित 4- टीयर व्यवस्था में रिजर्व बैंक ने टॉप टीयर में 3-4 बड़े बैंकों को उनकी विदेशी शाखाओं समेत रखने का प्रस्ताव दिया है, जिनकी देश और विदेश दोनों स्थानों पर उपस्थिति हो.

• टीयर 4 में निजी मालिकाना हक वाले लोकल बैंक और सहकारी बैंकों को शामिल करने का प्रस्ताव है.

• पत्र में कहा गया है कि टीयर 2 में मध्यम आकार के विस्तृत अर्थव्यवस्था वाले बैंक शामिल होने हैं और उसके बाद टीयर 3 में पुराने निजी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों की एक श्रेणी होनी है.

• एकीकरण के मामले में आरबीआई ने सहकारिता के आधार पर नपे-तुले कदम की बात की है और इसे अनिवार्य न बनाने पर जोर दिया.

• मालिकाना हक मसले पर पेपर में एक बार फिर से सरकारी स्वामित्व को घटाकर 51 प्रतिशत से नीचे लाने की बात की गई, ताकि घाटा के बोझ से दबी सरकार को बैंकों को फंड देने के झंझट से बचाया जा सके. ज्यादातर बैंकों के पास निजी पूंजी जुटाने की आजादी नहीं है.

वायदा कारोबार एनएसईएल दूसरे चरण के भुगतान में भी असफल रही

कमोडिटी की ट्रेडिंग हेतु भारत के प्रमुख वायदा बाजारों में एक नेशनल स्पॉट एक्चेंज लिमिटेड (एनएसईएल , National Spot Exchange Limited, NSEL) वायदा बाजार नियामक वायदा बाजार आयोग के निर्देशानुसार निवेशकों को दिये जाने वाले दूसरे चरण का भी भुगतान करने में असफल रही. एनएसईएल को 27 अगस्त 2013 को निवेशकों को 174 करोड़ रुपये का भुगतान

करना था जबकि एनएसईएल मात्र 12.05 करोड़ का ही भुगतान कर पायी. साथ ही, एनएसईएल निवेशकों की बकाया राशियों का भुगतान करने के लिए ऋण भी ले रखा है.

विदित हो कि एनएसईएल 20 अगस्त 2013 को निवेशकों को किये जाने वाले भुगतान की पहली किस्त भी देने मे असफल रही थी. पहली किस्त के अनुसार एनएलईएल को 174.72 करोड़ का भुगतान करना था जबकि वह 92.12 करोड़ का ही भुगतान कर पायी थी.

क्या है मामला?

नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) को सरकार के निर्देश के बाद इस महीने की शुरूआत से अपने कारोबार को बंद करना था क्योंकि इस वायदा बाजार ने सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया था. जिसके परिणामस्वरूप एनएसईएल ने अपने निवेशकों को सात महीने के भीतर 5600 करोड़ रुपये चुकाने की योजना बाजार नियामक वायदा बाजार आयोग को सौंपी थी.

निवेश संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की 36 परियोजनाओं को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली निवेश संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीआई , Cabinet Committee On Investment, CCI) ने इंफ्रास्ट्रक्टर क्षेत्र की 36 परियोजनाओं को 26 अगस्त 2013 को मंजूरी दी. इन तीन दर्जन परियोजनाओं में निवेश की जाने वाली कुल राशि लगभग 1.83 लाख करोड़ रुपये है. सीसीआई द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की मंजूर की गयी 36 परियोजनाओं में 18 विद्युत परियोजनाएं हैं जिनमें कुल 83772 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है जबकि ढांचागत क्षेत्र की नौ परियोजनाओं हैं जिनकी निवेश की संभावित राशि 14082 करोड़ रुपये है.

निवेश संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के बारे में केंद्रीय वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कहा, “सरकार की सर्वप्रथम प्राथमिकता है निवेश के चक्र को पुनः आरंभ करना जो कि अब शुरु हो चुका है और इसे आगे भी जारी रखेंगे. साथ ही, जिन 18 विद्युत परियोजनाओं के लिए मंजूरी दी गयी उनके लिए बैंकों से 30000 हजार करोड़ रुपये पहले ही आवंटित किये जा चुके हैं. निवेश संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने इन परियोजनाओं से संबंधित सभी मंत्रालयों को इन परियोजनाओं हेतु आवश्यक मजूरी 60 दिनों के भीतर देने के निर्देश दिये.

केवाईसी नियमों के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के छह बैंकों पर जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी, Know your customer, KYC) नियमों तथा मनी लांड्रिंग रोधक नियमों के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के छह बैंकों पर 6.5 करोड़

रुपए का जुर्माना लगाया. ये बैंक हैं-आईडीबीआई बैंक, देना बैंक. इलाहाबाद बैंक, बैंक आफ महाराष्ट्र और कारपोरेशन बैंक और इंडियन बैंक. आरबीआई ने इसकी जानकारी मुंबई में 23 अगस्त 2013 को दी. देना बैंक पर दो करोड़ रुपए, कारपोरेशन बैंक पर डेढ़ करोड़ रुपए का आईडीबीआई बैंक और इंडियन बैंक पर एक-एक करोड़ रुपए का, इलाहाबाद बैंक और बैंक आफ महाराष्ट्र पर 50-50 लाख रुपए का जुर्माना लगा गया है. भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल और मई 2013 के दौरान इन बैंकों के लेखा खातों, आंतरिक नियंत्रण, अनुपालन प्रणाली और प्रक्रियाओं की जांच के बाद यह जुर्माना लगाया.

यद्यपि भारतीय रिजर्व बैंक (केंद्रीय बैंक) ने कहा है कि जांच में प्रथम दृष्टया मनी लांड्रिंग का कोई मामला सामने नहीं आया है. रिजर्व बैंक ने कहा कि जांच में नियमन और दिशानिर्देशों के उल्लंघन की ही बात सामने आई है.

विदित हो कि इससे पहले भी भारतीय रिजर्व बैंक ने इसी तरह के उल्लंघन के मामलों में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक आफ बड़ौदा तथा बैंक आफ इंडिया सहित कुल 25 बैंकों पर जुर्माना लगाया था. भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के इंडसइंड बैंक की भी जांच की है और उससे स्पष्टीकरण मांगा गया है.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ट्राई व पीसीआई से मीडिया में एफडीआई पर राय मांगी

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बार फिर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से प्रसारण क्षेत्र में विदेशी निवेश सीमा के संदर्भ में गठित निकाय के बारे में अपनी टिप्पणी भेजने का आग्रह किया. ट्राई को लिखे पत्र में मंत्रालय ने प्रसारण क्षेत्र में मौजूदा एफडीआई सीमा की समीक्षा के संदर्भ में वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार पत्र के बारे में ट्राई से टिप्पणी मांगी. ट्राई को भेजे पत्र में उसकी सिफारिशें ट्राई कानून 1997 की धारा 11(1) (ए) (2) और (4) तहत मांगी गई, जिसमें सेवाप्रदाताओं को लाइसेंस की शर्तें और दूरसंचार सेवाओं की क्षमता बढ़ाने एवं प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के उपाय शामिल हैं.

इसके साथ ही एक ऐसे ही पत्र के जरिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय प्रेस परिषद से भी पीसीआई कानून 1978 की धारा 13 के तहत प्रिंट मीडिया में एफडीआई की मौजूदा सीमा पर विचार मंगाए हैं. ये सुझाव प्रिंट मीडिया में एफडीआई की मौजूदा सीमा पर नीति की समीक्षा के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय की ओर से प्राप्त पत्र के संदर्भ में मंगाए गए हैं.

विदित हो कि वित्त मंत्रालय ने समाचार क्षेत्र में एफआईपीबी के जरिए मौजूदा 26 प्रतिशत की एफडीआई सीमा को बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा. गैर-समाचार क्षेत्र में एफआईपीबी के जरिए मौजूदा 100 प्रतिशत एफडीआई सीमा को अब एफआईपीबी की बिना मंजूरी के ही 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ट्राई व पीसीआई से मीडिया में एफडीआई पर राय मांगी

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बार फिर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से प्रसारण क्षेत्र में विदेशी निवेश सीमा के संदर्भ में गठित निकाय के बारे में अपनी टिप्पणी भेजने का आग्रह किया. ट्राई को लिखे पत्र में मंत्रालय ने प्रसारण क्षेत्र में मौजूदा एफडीआई सीमा की समीक्षा के संदर्भ में वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार पत्र के बारे में ट्राई से टिप्पणी मांगी. ट्राई को भेजे पत्र में उसकी सिफारिशें ट्राई कानून 1997 की धारा 11(1) (ए) (2) और (4) तहत मांगी गई, जिसमें सेवाप्रदाताओं को लाइसेंस की शर्तें और दूरसंचार सेवाओं की क्षमता बढ़ाने एवं प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के उपाय शामिल हैं. इसके साथ ही एक ऐसे ही पत्र के जरिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय प्रेस परिषद से भी पीसीआई कानून 1978 की धारा 13 के तहत प्रिंट मीडिया में एफडीआई की मौजूदा सीमा पर विचार मंगाए हैं. ये सुझाव प्रिंट मीडिया में एफडीआई की मौजूदा सीमा पर नीति की समीक्षा के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय की ओर से प्राप्त पत्र के संदर्भ में मंगाए गए हैं.

विदित हो कि वित्त मंत्रालय ने समाचार क्षेत्र में एफआईपीबी के जरिए मौजूदा 26 प्रतिशत की एफडीआई सीमा को बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा. गैर-समाचार क्षेत्र में एफआईपीबी के जरिए मौजूदा 100 प्रतिशत एफडीआई सीमा को अब एफआईपीबी की बिना मंजूरी के ही 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया.

रुपया अपने सर्वकालिक न्यूनतम स्तर पर

भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट का दौर लगातार जारी है और सरकार एवं विभिन्न निकायों के प्रयासों के विशेष असर नही पड़ने के बीच भारतीय रुपये में भी विदेशी मुद्राओं के मुकाबले गिरावट लगातार जारी है. डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 21 अगस्त 2013 को अपने सर्वकालिक न्यूनतम स्तर रुपये 64.11 प्रति डॉलर तक गिर गया जो कि रुपये के इतिहास का अब तक सबसे निचला स्तर है. साथ ही, भारतीय रुपये विदेशी मुद्रा पौंड के मुकाबले भी लगातार गिरता जा रहा है; 21 अगस्त 2013 को यह 100 रुपये प्रति पौंड से भी नीचे चला गया. मुद्रा बाजार में भारतीय रुपये की प्रमुख विदेशी मुद्राओं विशेषकर डॉलर के मुकाबले गिरावट के मुख्य कारणों में शामिल हैं-

- चालू वित्तीय घाटा
- भारतीय अर्थव्यवस्था की लगातार खराब होती स्थिति
- सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट
- रेटिंग घटने की संभावना

- जोखिम घटने से डॉलर सूचकांक में मजबूती
- लगातार बढ़ता आयात
- आरबीआई तथा सरकार के प्रोत्साहन उपायों का गिरता प्रभाव
- कमजोर औद्योगिक उत्पादन तथा उच्च ब्यार दरें
- अपर्याप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी संस्थागत निवेश
- सरकार की अधिनियामक तथा नीतिगत अक्षमता
- उभरते बाजारों पर यूरोपीय संकट का प्रभाव
- चीन में मंदी से कमोडिटी आधारित अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव
- सुरक्षित तथा तरल बांडों की ओर मुद्रा प्रवाह का बढ़ना

वायदा बाजार आयोग ने एनएसईएल को निवेशकों के सेटलमेंट हेतु नोटिस जारी किया

देश के कमोडिटी बाजारों में एक नेशनल स्पॉट एक्चेंज (एनएसईएल, National Spot Exchange Limited, NSEL) को देश के वायदा बाजार नियामक वायदा बाजार आयोग (एफएमसी, Future Market Commission, FMC) ने 21 अगस्त 2013 को नोटिस जारी करके निवेशकों के पैसे लौटाने हेतु अपने गोदामों में रखी गयी कमोडिटी को नीलाम करने के आदेश दिये. अपने नोटिस में वायदा बाजार नियामक एफएमसी ने एनएसईएल को यह भी निर्देश दिये कि यह अपने डिफॉल्टरों के वित्तीय दस्तावेज, सम्पत्तियों के दस्तावेज और चेकबुक आदि जब्त करे ताकि निवेशकों के पैसे लौटाये जा सकें. एफएमसी ने अपने नोटिस में निर्देश दिया कि एनएसईएल गोदामों में रखी कमोडिटी स्टॉक एवं अपने डिफॉल्टरों की परिसम्पत्तियों को जब्त करने प्राप्त हुई राशि को एस्क्रो अकाउंट में जमा करे और निवेशकों को उनकी राशि लौटाने से पूर्व एफएमसी से मंजूरी ले.

विदित हो कि एनएसईएल को अगस्त 2013 माह की शुरूआत से अपना कारोबार बंद करने को कहा गया था जिसके कारण एनएसईएल ने सात माह के भीतर निवेशकों के पैसे लौटाने की योजना एफएमसी को सौंपी थी, लेकिन एनएसईएल निवेशकों को रकम लौटाने के पहले चरण में ही तय राशि लौटाने में नाकाम रही थी. इसी के चलते एनएसईएल ने 20 अगस्त 2013 को अपने सीईओ व एमडी और छह अन्य शीर्ष अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया था. उनमें मुख्य वित्तीय अधिकारी, विभिन्न विभागों के सहायक उपाध्यक्ष व प्रबंधक शामिल हैं.

एनएसईएल (National Spot Exchange Limited, NSEL)

एनएसईएल भारत के वायदा बाजारों (Commodity Exchanges) में से एक है. यह फाइंनेंशियल टेक्नोलॉजीस इंडिया लिमिटेड और नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (नैफेड) का संयुक्त उपक्रम है. एनएसईएल ने विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं में लाइव ट्रेडिंग की शुरूआत 15 अक्टूबर 2008 से की थी.

वायदा बाजार आयोग (एफएमसी , Future Market Commission, FMC)

वायदा बाजार आयोग भारत में फॉर्वर्ड एवं वायदा का एक मुख्य नियामक प्राधिकारी है तथा फॉरवर्ड संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के तहत 1953 में स्थापित एक सांविधिक निकाय है. वायदा बाजार आयोग उपभोक्ता मामले,खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,भारत सरकार के देखरेख में कार्य करता है. वायदा बाजार आयोग में न्यूनतम दो तथा अधिकतम चार सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है. वायदा बाजार आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा ही की जाती है.

वायदा बाजार आयोग के कार्य इस प्रकार हैं:

(क) किसी भी संघ की मान्यता या मान्यता की वापसी के संबंध में या वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम 1952 के क्रियान्वयन से उत्पन्न किसी भी अन्य मामले के संबंध में केन्द्र सरकार को सलाह देने के लिए.

(ख) वायदा बाजार को निगरानी में रखने और उससे सम्बंधित कार्रवाई करने के लिए,जो की आवश्यक हो सकता है,या इस अधिनियम के द्वारा या अंतर्गत उसे सौंपे शक्तियों के प्रयोग में.

(ग) इकट्ठा करने और जब भी आयोग यह आवश्यक समझता है,वस्तुओं के व्यापार की शर्तों के बारे में जानकारी प्रकाशित करने के लिए जो की अधिनियम के किसी भी प्रावधानों से लागू किया जाता है जिनमे आपूर्ति,मांग और कीमतों के बारे में जानकारी भी शामिल है और इस तरह के सामान से संबंधित वायदा बाजार की कार्यशैली पर आवधिक विवरण (रिपोर्ट) केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करना;

(घ) सामान्यतः वायदा बाजार के काम और संगठन में सुधार लाने की दृष्टि से सिफारिशें करना;

(ङ) किसी भी मान्यता प्राप्त संघ या पंजीकृत संस्था या इस तरह के सहयोग से बने किसी भी सदस्य के खातों और अन्यदस्तावेजों के निरीक्षण का कार्य करने के लिए जब भी यह आवश्यक समझे.

आरबीआई ने तरलता बढ़ाने हेतु एलएलआर को 1.5 प्रतिशत बढ़ाया

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की तरलता बढ़ाने एवं उनके निवेश पोर्टफोलियो को रुपये की गिरती साख को बचाने के विभिन्न प्रयासों के दौरान हुए नुकसानों की भरपाई करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 20 अगस्त 2013 को वैधानिक नकदी अनुपात (एसएलआर, Statutory Liquidity Ratio, SLR) को मौजूदा 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 24.5 प्रतिशत कर दिया. आरबीआई द्वारा 1.5 फीसदी की बढ़ोत्तरी से बैंक अब अपनी जमाओं व सरकारी बांडों का 24.5 प्रतिशत तक रख सकते हैं. आरबीआई के इस कदम के परिणामस्वरूप बैंकों के पास अब पहले से कहीं अधिक पूंजी ऋण देने के लिए उपलब्ध होगी. आरबीआई ने अपने जारी नोट में कही कि मुद्रास्फीति को रोकने व बाजार से नकदी की मात्रा कम करने के प्रयासो के तहत कई कदम हाल में उठाये जा चुके हैं लेकिन हमे यह सुनिश्चित करना है कि इन प्रयासों का विपरीत प्रभाव ऋण की उपलब्धता पर न पड़े.

विदित हो कि बाजार से नकदी कम करने व विदेशी मुद्राओं के मुकाबले रुपये की गिरती साख को रोकने के प्रयासों के तहत आरबीआई के उपायों चलते वित्त बाजार पर काफी नकारात्मक असर रहा जिसके कारण कई उद्योगों में मंदी की सामना करना पड़ा है. इसके साथ ही आरबीआई ने घोषणा की कि विदेशी मुद्राओं के मुकाबले रुपये की गिरती कीमत को रोकने के लिए यह 23 अगस्त 2013 को खुले बाजार से 8000 करोड़ रुपये के सरकारी बाँडों की भी खरीद करेगा.

विदित हो कि 28 अगस्त 2013 को भारतीय रुपया अपने सर्वकालिक न्यूनतम स्तर 68.80 रुपये प्रति डॉलर तक पहुँच गया था.

औषधि निर्माण के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में बदलाव करने का सरकार का निर्णय

केंद्र सरकार औषधि निर्माण के क्षेत्र में मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में बदलाव लाना चाहती है, ताकि विदेशी कम्पनियों द्वारा देसी कम्पनियों के अधिग्रहण की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर घरेलू जैनरिक उद्योग को बचाया जा सके. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस उद्देश्य के लिए 16 अगस्त 2013 को नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की. बैठक में निर्णय किया गया कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इस सिलसिले में जल्द ही सलाह मशविरे की प्रक्रिया शुरू करे.

विदित हो कि बैठक के बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनन्द शर्मा ने कहा कि विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड के समक्ष प्रस्तावों को मौजूदा नीति के तहत देखा जाना है.

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी)

भारत में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जुड़े उन प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए एक सिगल विंडो का काम करता है जिन पर सीधे तौर पर एफडीआई की स्वीकृति नहीं होती. इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय कंपनियों,अप्रवासी भारतियों तथा अन्य विदेशी निवेशकों के माध्यम से देश में

निवेश की सुविधा प्रदान करके भारत तथा विदेश में निवेश संवर्धन कार्यकलापों की शुरूआत करके भारत में एफडीआई का संवर्धन करना है. एफआईपीबी में विभिन्न मंत्रालय के सचिवों के साथ-साथ आर्थिक मामलों के विभाग एवं वित्त मंत्रालय के सचिव अध्यक्ष के रूप में होते हैं. यह अंतरमंत्रालीय निकाय देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा, उच्चतम सीमा, कारकों पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के तहत करता है. वित्त मंत्रालय एफआईपीबी के अधिकतम 1200 करोड़ रुपए तक के प्रस्तावों पर की गई सिफारिशों को मंजूरी प्रदान करता है. ऐसे प्रस्तावों जिनका मूल्य 1200 करोड़ रुपए से अधिक होता है उनके लिए आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति की स्वीकृति लेनी होती है.

घाटा उठाने वाले केंद्रीय उपक्रमों के कर्मचारियों को वेतन भुगतान हेतु निधियों के प्रस्ताव को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने घाटा उठा रहे केंद्रीय उपक्रमों के कर्मचारियों हेतु 128.26 करोड़ रुपये के गैर योजना बजट समर्थन के प्रस्ताव को 13 अगस्त 2013 को अनुमोदित किया. इस राशि का इस्तेमाल भविष्यनिधि, ग्रेच्युएटी, पेंशन आदि के भुगतान के लिए किया जाना है. भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत आने वाले इन उपक्रमों के नाम हैं :

- हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
- एचएमटी लिमिटेड
- एचएमटी (वॉचेज़) लिमिटेड
- एचएमटी (चिनार वॉचेज़) लिमिटेड
- नगालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड
- त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
- तुंगभद्रा स्ट्रील प्रॉडक्टस लिमिटेड
- नेपा लिमिटेड, एचएमटी बीयरिंग लिमिटेड
- हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स लिमिटेड

विदित हो कि वेतन और अन्य भुगतान के लिए निधियां उपलब्ध कराने से कर्मचारियों की कठिनाइयां दूर हो सकेंगी और उनके प्रति उपक्रमों की कानूनी जिम्मेदारी भी पूरी होनी है.

सुईस ने वित्तवर्ष 2013-14 में भारत के विकास अनुमानों को घटाया

वैश्विक स्तर पर अपनी क्रेडिट सेवाओं के लिए विख्यात प्राइवेट फर्म क्रेडिट सुईस ने 13 अगस्त 2013 को जारी अपने शोध नोट में भारत की जीडीपी के विकास की दर को वित्तीय वर्ष 2013-14 में 6.5 प्रतिशत से घटकर 6.0 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया. न सिर्फ वित्तवर्ष 2013-14 बल्कि क्रेडिट सुईस ने वर्ष 2014-15 के लिए भी भारत के विकास अनुमान को 7.5 प्रतिशत से कम होकर 7.0 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया. क्रेडिट सुईस ने अपने शोध नोट में कहा, "भारतीय अर्थव्यवस्था में चारों ओर निराशा का वातावरण मौजूद है इसलिए निवेश संबंधी परिस्थितियां जटिल होती जा रही हैं. ज्यादातर उद्योग समूहों एवं जीडीपी में बड़ी हिस्सेदारी वाले क्षेत्रों का उत्पादन घटा है. इन सभी के चलते आर्थिक परिस्थितियां कठिन हो रही हैं." वर्तमान कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बारे में क्रेडिट सुईस ने अपनी शोध रिपोर्ट में नकारात्मक वातावतरण के साथ-साथ कई कारकों को भी जिम्मेवार माना है जैसे कि मुद्रा विमिनय बाजार में रुपये की गिरती साख, बिजनेस एवं उपभोक्ताओं का गिरता भरोसा, आरबीआई के तरलता कम करने संबंधी प्रयास, आदि. हालांकि क्रेडिट सुईस ने अपने शोध नोट मे भारतीय अर्थव्यवस्था के सकारात्मक पक्ष का जिक्र करते हुए कहा, "भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत परिस्थितियां वर्ष 2012-13 के मुकाबले 2013-14 मे काफी बेहतर हैं जिसके परिणामस्वरूप योजनाबद्ध प्रयासों से विकास की गति बढ़ाई जा सकती है." नोट में कहा गया है कि कठिन दौर में भी थोक मूल्य सूचकांकों पर आधारित मुद्रास्फीति में कमी के संकेत निस्संदेह आशाजनक हैं लेकिन अन्य कड़ी परिस्थितियां ज्याद प्रभावी हो रही हैं.

विदित हो कि फरवरी 2013 में भारत सरकार की ओर से जारी किये आकड़ों में वर्ष 2013-14 के लिए विकास अनुमानों को 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था.

अन्य अनुमान

हाल ही में आरबीआई ने भी वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही की समीक्षा में वर्ष 2013-14 में भारत की विकास दर के 5.7 प्रतिशत से घटकर 5.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था. पिछले महीने एशियाई विकास बैंक ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की दर को अपने पहले के अनुमान 6 प्रतिशत से घटाकर 5.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था.

रुपये की गिरती कीमत को रोकने हेतु विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन पर आरबीआई का प्रतिबंध

भारतीय रिजर्व बैंक तथा केंद्र सरकार के तमाम उपायों के बावजूद विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपये की लगातार गिरती कीमत रुक नही रही है. आरबीआई ने इसी दिशा में 13 अगस्त 2013 को कुछ और कदम उठाये. नये उपायों में सबसे प्रमुख है विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन पर लगायी गयी आंशिक रोक. आरबीआई ने

स्वचालित मार्ग (Automatic Route) के तहत घरेलू कंपनियों के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई, Overseas Direct Investment, ODI) की सीमा को उनके निवल मूल्य (Net Worth) का 100 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है. पहले यह सीमा निवल मूल्य का 400 प्रतिशत थी. आरबीआई ने इस प्रतिबंध के बारे में स्पष्ट किया कि यह सीमा घरेलू कंपनियों द्वारा विदेश में उर्जा क्षेत्र में गैर निगमित इकाईयों की स्थापना के लिए ओडीआई स्कीम के तहत भेजी जाने वाली राशि पर भी यह सीमा लागू होगी. आरबीआई ने अपने एक अन्य उपाय के तहत नागरिकों द्वारा उदारीय विप्रेषण योजना (Liberalised Remittance Scheme, LRS Scheme) के अंतर्गत विदेश भेजी जाने वाली राशि की सीमा 2 लाख डॉलर प्रतिवर्ष से घटाकर 75000 डॉलर प्रतिवर्ष कर दी. केंद्रीय बैंक ने विदेश मुद्रा के बहिर्गमन को रोकने हेतु एक और कदम यह भी उठाया कि विदेशों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अचल संपत्तियों के क्रय के लिए एलआरएस के उपयोग की अनुमति नहीं होगी.

विदित हो कि 14 अगस्त 2013 को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने सर्वकालिक न्यूनतम स्तर 61.43 रुपये प्रति डॉलर तक चला गया.

केंद्र सरकार ने सोने, चांदी और प्लेटिनम पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया

केंद्र सरकार ने चालू खाता घाटे को कम करने के लिए सोने, चांदी और प्लेटिनम पर सीमा शुल्क 13 अगस्त 2013 को बढ़ा दिया. सोने और प्लेटिनम पर इसे 8 प्रतिशत से बढा कर 10 प्रतिशत कर और चांदी पर सीमा शुल्क 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया. चालू खाता घाटे पर नियंत्रण के सरकार के उपायों के तहत ऐसा किया गया. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कच्चे सोने के बिस्कुट (कोर बिस्कुट)और उसके अयस्क पर भी आयात शुल्क 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत किया. कच्ची चांदी की सिल्ली पर शुल्क 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत किया गया. डोर बिस्कुट सोने और चांदी की मिश्र धातुएं होती हैं, जिन्हें आयात कर उनका परिशोधन किया जाता है. इसलिए परिशोधित सोने के बिस्कुटों पर उत्पाद शुल्क 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत किया गया. इसी तरह अयस्क से तैयार चांदी पर भी आयात शुल्क 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत किया गया. विदित हो कि केंद्र सरकार को उम्मीद है कि इससे इन कीमती धातुओं का आयात घटेगा और वह सीएडी को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.7 प्रतिशत तक सीमित कर सकेगी. वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान सीएडी 4.8 प्रतिशत रहा था. इन कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने से राजकोष में अतिरिक्त 4830 करोड़ रुपये का राजस्व आना है. डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमत को रोकने के लिए आरबीआई ने 22000 करोड़ के बांड की नीलामी की.

भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमत को रोकने के लिए एक और प्रयास करते हुए 12 अगस्त 2013 को 22000 करोड़ रुपये मूल्य के बांडों की नीलामी की. आरबीआई ने यह कदम अर्थव्यवस्था से तरलता को कम करने के माध्यम से विदेश मुद्रा विनिमय में उतार-चढ़ाव को जांचने के

लिए किया. आरबीआई के द्वारा 22000 करोड़ मूल्य नीलाम किये गये सरकारी बांड अल्प अवधि के हैं तथा यह नीलामी आरबीआई के उस घोषणा का पहला प्रयास है जिसमें कहा गया था कि विदेश मुद्रा विनिमय की अस्थिरता को रोकने के नकदी प्रबंधन हुंडियां (Cash Management Bills) के 22000 करोड़ रुपये के मूल्य के सरकारी बांडों की नीलामी हर सप्ताह (प्रत्येक सोमवार) की जाएगी. विदित हो कि नकदी प्रबंधन हुंडियों की प्रकृति राजकोष के सामान्य हुंडिया के ही समान होती हैं. पहले समूह में नीलाम हुएं बांडों की परिपक्वता अवधि 34 दिन है.

सेबी द्वारा अनधिकृत सामूहिक निवेश योजनाओं को 'फर्जीवाड़ा एवं अनुचित व्यापारिक चलन' घोषित

देश भर में चल रही व्यक्तिगत स्तर पर चल रही विभिन्न प्रकार की अनधिकृत सामूहिक निवेश योजनाओं को बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने फर्जीवाड़ा एवं अनुचित व्यापारिक चलन घोषित करने का फैसला किया. सेबी इस संबंध में 12 अगस्त 2013 को निर्देश जारी किया. सेबी ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया कि नियामक से आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना सामूहिक निवेश की किसी भी योजना को क्रियान्वित या संचालित नहीं किया जा सकता है. हाल ही में सेबी को यह अधिकार दिया गया कि गैर-सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा पूंजी जुटाने की उन योजनाओं (पोंजी योजनाएं या चिट फंड) को नियमित कर सकती है जिनमें 100 करोड़ या अधिक राशि का निवेश हो रहा हो. सेबी के द्वारा अनधिकृत सामूहिक निवेश योजनाओं के संचालन पर कड़ा दंड लगाया जा सकता है.

चिट फंड (CHIT FUND)

घरेलू स्तर का निवेश संघ जिनके माध्यम से आम तथा छोटे-छोट निवेशक एक समूह बनाकर निवेश करते हैं जिनमें से कई के तो बैंक खाते तक नहीं होते. हमारे देश में अभी तक इस तरह की स्कीमों के लिए चिट फंड अधिनियम 1982 रहा है. चिट फंड योजनाओं का व्यवस्थापन सगठित वित्तीय संस्थाओं या असंगठित समूहों या किसी व्यक्ति, मित्र आदि द्वारा चलाया जा सकता है. केरल राज्य में चिट फंड स्कीमों को 'चिट्टी' नाम से संबोधित किया जाता है. केरल सरकार की एक कंपनी 'केरल स्टेट फाइनेंसियल एंटरप्राइजेज' का मुख्य कारोबार 'चिट्टी' है.

जुलाई 2013 में भारत से निर्यात के आकड़ों में सुधार लेकिन व्यापार घाटा बढ़ा

विभिन्न प्रकार की नकारात्मक आर्थिक परिस्थितियों के बीच जुलाई 2013 माह में देश का कुल निर्यात की वृद्धि दर पिछले वर्ष के इसी माह के मुकाबले 11.64 फीसदी अधिक रही. दूसरी ओर देश का आयात जुलाई 2013 माह में पिछले वर्ष के इसी माह के मुकाबले 6.2 फीसदी रही. वाणिज्य मंत्रालय ने जुलाई 2013 माह के आयात-निर्यात से संबंधित आकड़े 12 अगस्त 2013 को जारी किये. जुलाई 2013 में देश का कुल निर्यात 25834.46 मिलियन अमरीकी डॉलर (154426.51 करोड़ रुपये) का हुआ जबकि जुलाई 2012 के दौरान यह आकड़ा 23140.43 मिलियन डॉलर (128417.33 करोड़ रुपये) था. इसी प्रकार जुलाई, 2013 के दौरान आयात 38102.56 मिलियन अमरीकी डॉलर (227759.60 करोड़ रुपये) का रहा जबकि जुलाई 2012 में यह आकड़ा 40619.45 मिलियन अमरीकी डॉलर (225416.80 करोड़) तक पहुंचा था. हालांकि निर्यात में सुधार तथा आयात में कमी के बावजूद देश का व्यापार घटा बढ़ा है. वर्तमान वित्त वर्ष के अप्रैल से जुलाई 2013 के बीच देश का अनुमानित व्यापार घाटा 62448.16 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा जो कि वर्ष 2012-13 के दौरान अप्रैल से जुलाई के बीच 59695.75 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक रहा. आयात-निर्यात से संबंधित आकड़ों को जारी करते हुए वित्त मंत्रालय के सचिव एस आर राव ने कहा, "सरकार के द्वारा दिये गये निर्यात के प्रोत्साहन उपायों से आने वाले समय में स्थिति में अधिक सुधार होगा. वर्तमान वित्त वर्ष में हमने 10 प्रतिशत निर्यात वृद्धि का लक्ष्य रखा है. उभरते बाजारों जैसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, आसियान तथा सुदूर पूर्व के देशों में निर्यात को बढ़ावा देने से देश के विदेशी व्यापार में सुधार होगा."

निर्यात-आयात (अमरीकी मिलियन डॉलर)

(अस्था0ई)		
	जुलाई	अप्रैल-जुलाई
निर्यात (पुनर्निर्यात सहित)		
2012-13	23140.43	96632.20
2013-14	25834.46	98290.13
वृद्धि % 2013-14/ 2012-2013	11.64	-1.72
आयात		
2012-13	40619.45	156327.95
2013-14	38102.56	160738.29
वृद्धि % 2013-14/ 2012-2013	-6.20	2.82
व्या-पार संतुलन		
2012-13	-17479.02	-59695.75
2013-14	-12268.10	-62448.16

निर्यात-आयात : (रु. करोड़)

(अस्था1ई)	जुलाई	अप्रैल-जुलाई
निर्यात (पुनर्निर्यात सहित)		
2012-13	128417.33	526301.34
2013-14	154426.51	559531.29
वृद्धि % 2013-14/ 2012-2013	20.25	6.31
आयात		
2012-13	225416.80	851289.60
2013-14	227759.60	911927.33
वृद्धि % 2013-14/ 2012-2013	1.04	7.12
व्याधपार संतुलन		
2012-13	-96999.47	-324988.26
2013-14	-73333.09	-352396.04

स्रोत- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

जून 2013 में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर में गिरावट

भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति के प्रमुख सूचकों में से एक औद्योगिक उत्पादन की विकास दर जून 2013 माह में 2.2 प्रतिशत नकारात्मक रही. केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 12 अगस्त 2013 को औद्योगिक उत्पादन से संबंधित आद्योगिक उत्पादन सूचकांक के त्वरित आकलन जारी किये. जून 2013 के लिए जारी किये गये आद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए वर्ष 2004-05 की कीमतों के आधार पर जारी किये गये. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी जून 2013 के लिए सामान्य औद्योगिक सूचकांक 164.3 है जो कि पिछले वर्ष के जून माह के मुकाबले 2.2 प्रतिशत कम है. इसी प्रकार अप्रैल से जून 2013 की अवधि अर्थात पहली तिमाही में संचयी वृद्धि दर पिछले वर्ष के इसी अवधि के दौरान वृद्धि दर के मुकाबले 1.1 प्रतिशत कम रही. देश के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मे नकारात्मक वृद्धि का प्रमुख कारण 22 विनिर्माण क्षेत्रों में से 13 में नकारात्मक वृद्धि दर होने के कारण रही. फर्नीचर, विनिर्माण एनईसी में सबसे ज्यादा नकारात्मक वृद्धि 23.8 प्रतिशत रही.

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (INDEX FOR INDUSTRIAL PRODUCTION, IIP)

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है. चालू वित्त वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पादन के आकड़ों को जारी करने के लिए वर्ष 2004-05=100 को आधार बनाया गया है. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को 16 स्रोत विभागों से प्राप्त

पर्यावरण | पारिस्थितिकी

देखरेख और भंडारण की सुविधाओं के अभाव में जीवाश्मों पर नष्ट होने का खतरा

कैलिफोर्निया आधारित भूगर्भविज्ञानी एवं हिमालय की प्रागैतिहासिक चट्टानों का शोध करने वाले निगेल हगेस के अनुसार आधुनिक तकनीक से देखरेख और भंडारण की सुविधाओं के अभाव में भारत में करोड़ों वर्ष पुराने जीवाश्मों पर नष्ट होने का खतरा मंडरा रहा है. भारत की अधिकांश भूगर्भीय और जीवाश्मीय धरोहरें अकादमिक संस्थानों में रखी गई हैं. भारत में इन जीवाश्मों को भारतीय विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्यों ने एकत्र किया है. निगेल हगेस के अनुसार चूंकि ये संस्थान संग्रहालय नहीं है इसलिए वे जीवाश्मों का रखरखाव नहीं कर सकते.

विदित हो कि भारत जीवाश्म वाली चट्टानों के संग्रह के मामले में समृद्ध है जो करोड़ों साल पुरानी हैं और ये जीवन की उत्पत्ति और विकास को समझने के लिए बहुत अहम हैं. भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण संग्रहालय कोलकाता भारत में एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां देश के विभिन्न हिस्सों के जीवाश्म, खनिज और चट्टानों के नमूनों के संग्रह रखे हुए हैं.

जीवाश्म

पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाये जाते हैं उन्हें जीवाश्म (जीव + अश्म = पत्थर) कहते हैं. जीवाश्म से कार्बनिक विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है. इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान या पैलेन्टोलॉजी कहते हैं.

जीवाश्म को अंग्रेजी में फ़ॉसिल कहते हैं. इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द "फ़ॉसिलस" से है, जिसका अर्थ "खोदकर प्राप्त की गई वस्तु" होता है. जीवाश्म मुख्यतः भूपर्पटी के अवसादी शैलों में पाए जाते हैं.

केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने शार्क के संरक्षण हेतु नई नीति घोषित की

केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने शार्क मछली को बचाने के लिए 'फिन्स नैचुरली अटैच्ड (Fins Naturally Attached)' नीति घोषित की. नई घोषित नीति के अनुसार, मत्स्य पालन में संलग्न व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा शार्कों को बिना उनके पंखों को नुकसान पहुंचाये समुद्र तटीय इलाकों में छोड़ा जाना है. इसकी सूचना अगस्त 2013 के चौथे हफ्ते में दी गयी. इस नीति के माध्यम से शार्कों के पंखों को काटे जाने की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी. मछुआरे पकड़ी गयी शार्कों के पंखों को काट लेतें हैं और अधमरी शार्क मछलियों को पीड़ादायक मौत के लिए छोड़ देते हैं.

भारत को हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में शार्कों के मारे जाने वाले देशों की श्रेणी में दूसरे स्थान पर रखा गया. इसके पीछे कारण है कि भारत शार्कों को मांस हेतु काफी बड़ी मात्रा में शिकार किया जाता है. दूसरी तरफ, शार्कों के पंखों के सूप की लगातार बढ़ती मांग के कारण शार्कों को उनके पंखों के लिए भी शिकार किया जा रहा है. मछुआरे शार्कों के पंखों का निर्यात भी करते हैं.

शार्कें समुद्री जैव-श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ी हैं तथा समुद्री पारिस्थितिकीय तंत्र में मुख्य भूमिका निभाती हैं. अन्य मछलियों की तुलना में शार्कें कम बच्चे पैदा करती हैं जिससे शार्कों की ज्यादातर प्रजातियां भारत में लुप्त होने के कगार पर हैं.

लैबियोनाइन मछली की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में पायी गयी

गर्म मौसम से उग्र मनोवृत्ति का विकास होता है

अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा तापमान के मानव स्वभाव पर पड़ने वाले असर पर किये गये अध्ययन पर प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण निरंतर बढ़ रहे तापमान के कारण समूचे विश्व के लोगों की मनोवृत्ति उग्र होती जा रही है. यह रिपोर्ट ऑनलाइन जर्नल साइंस में 1 अगस्त 2013 को प्रकाशित हुई. कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया कि आक्रामक कार्यों, जैसे विभिन्न प्रकार के अपराध, युद्ध, आदि के होने की संभावना तापमान में प्रत्येक डिग्री बढोत्तरी के साथ बढ़ती जाती है.

वैज्ञानिकों ने अमेरिका के ऐतिहासिक साम्राज्यों के पतन, हाल के युद्धों, अपराधों के बढ़ने की दर और प्रयोगशाला में छद्म परिस्थितियों के 60 से अधिक अध्ययनों का परीक्षण किया. अपने अध्ययनों में वैज्ञानिकों ने पाया कि शताब्दियों के बढ़ने के साथ तापमान गर्म तथा शुष्क होते गये जिनसे उन परिस्थितियों के व्यक्ति अधिक आक्रामक होते गये. साथ ही, अध्ययन में संलग्न आर्थिक विशेषज्ञों के दल ने तापमान के बढ़ने के साथ विभिन्न प्रकार के अपराधों के होने की भविष्यवाणी का एक सूत्र भी विकसित किया. विशेषज्ञों ने अपने सूत्र से बताया कि तापमान के प्रत्येक डिग्री फॉरेनहाइट के बढ़ने के साथ अफ्रीका के भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के विभिन्न समूहों में संघर्ष की संभावना 10 से 14 फीसदी तक बढ़ जाती है.

उड़ीसा का भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान पर्यटकों के लिए पुनः खुला

उड़ीसा राज्य के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान को पर्यटकों के लिए 1 अगस्त 2013 से दोबारा खोल दिया गया. इस राष्ट्रीय उद्यान को 15 मई 2013 को मगमच्छों के नेस्टिंग काल (वह समय जबकि अंडे देने वाले जीव अपने अंडों से बच्चे निकलने के लिए उनकी देखभाल करते हैं) के दौरान के बंद कर दिया गया था. आमतौर पर मादा मगरमच्छ अपने नेस्टिंग काल के दौरान अपने अंडों की सुरक्षा को लेकर काफी आक्रामक हो जाती हैं जिससे बाहरी पर्यटकों के लिए खतरा पैदा हो जाता है. इसी कारण सुरक्षा की दृष्टि से भीरकानिका राष्ट्रीय उद्यान को ढाई महीने के लिए बंद कर दिया गया था. एक अनुमान के मुताबिक भीतरनिका राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 1600 खारे पानी के मगरमच्छ मौजूद हैं. मगरमच्छों में प्रजनन की क्रिया फरवरी से अप्रैल के बीच होती है जबकि इनका नेस्टिंग काल आमतौर पर मई में आरंभ होता है. एक मादा मगरमच्छ एक बार में औसतन 45 अंडे देती है. मगरमच्छों के अंडों से बच्चे 70-80 दिनों में बाहर निकलने लगते हैं. इस दौरान मादा मगरमच्छ अपने अंडों हेतु टहनियों, पत्तियों तथा मिट्टी से घोसले बनाती हैं.

भीतरकानिका राष्ट्रीय उद्यान (BHITARKANIKA NATIONAL PARK)

भीतरकानिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है. इसका कुल क्षेत्रफल 672 वर्ग किमी है. भीतरकनिका ब्राहमानी, बैतारानी तथा धामरा नदियों के मुहानों पर स्थित है और भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य से घिरा हुआ है. भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान को सितंबर 1998 में भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य के कुछ हिस्से में विकसित किया गया था. भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य का निर्माण 1975 में किया गया था.

विश्व में खारे पानी के सबसे बड़े मगमच्छ, जिसकी लंबाई 23 फीट है, की मौजूदगी के कारण भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 2006 में शामिल किया गया था.

भीरनिका को ऑलिव रिडले (Olive Ridley) नामक समुद्री कछुओं के विश्व के सबसे बड़े अड्डे के रूप में भी जाना जाता है.

विज्ञान | तकनीक

वैज्ञानिकों ने मलेरिया की पीएफएसपीजेड (PFSPZ) नामक एक नई वैक्सीन विकसित की

सनारिया इंक. रॉकविल, मेरीलैंड के वैज्ञानिकों ने मलेरिया की एक नई वैक्सीन विकसित की, जिसका नाम पीएफएसपीजेड (PfSPZ) है. यह वैक्सीन प्लाजमोडियम फाल्सीपेरम जाति के बीजाणुओं को कमजोर या नष्ट कर देती है. प्लाजमोडियम फाल्सीपेरम मलेरिया का बहुत खतरनाक परजीवी है. एक प्रारंभिक चरण के नैदानिक परीक्षण के अनुसार–यह वैक्सीन व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को सुरक्षित रखती है तथा मलेरिया संक्रमण के खिलाफ संरक्षण प्रदान करती है. यह साइंस जर्नल में प्रकाशित था.

मलेरिया

विश्व का पहला बोलने वाला रोबोट 'किरोबो' अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए रवाना

जापान ने विश्व के पहले बोलने वाले रोबोट 'किरोबो' को अंतरिक्ष में 4 अगस्त 2013 को भेजा. जापान के तनेगाशिमा द्वीप से एच2बी राकेट के जरिए रोबोट व अन्य सामान प्रक्षेपित किए गए. यह रोबोट 9 अगस्त 2013 को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में पहुंच जाना है. इसी के साथ जापान अंतरिक्ष में बोलने वाला रोबोट भेजने वाला विश्व का पहला देश बन गया. नौ महीने से ज़्यादा समय तक किरोबो की विश्वसनीयता को परखने के लिए उस पर कई परीक्षण किए गए. किरोबो का एक जुड़वा रोबोट 'मिराटा' धरती पर है. मिराटा द्वारा अपने जोड़ीदार में अंतरिक्ष में होने वाली किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी पर नज़र रखी जानी है.

किरोबो को अंतरिक्ष में भेजने का उद्देश्य

किरोबो एक शोध का हिस्सा है जिसके तहत यह देखा जाना है कि लंबे समय तक अकेले रहने वाले लोगों को मशीनें किस तरह से भावनात्मक सहारा दे सकती हैं.

किरोबो

रोबोट किरोबो 34 सेंटीमीटर लंबा है और इसका रंग काला और सफेद है. इस छोटे से मानवरूपी रोबोट का वज़न करीब एक किलो है और यह कई तरह की शारीरिक हरकतें कर सकता है.

• इसके डिज़ाइन की प्रेरणा मशहूर एनिमेटेड कैरेक्टर एस्ट्रो बॉय से ली गई है.

• किरोबो नाम 'उम्मीद' और 'रोबोट' के लिए जापानी शब्दों से बनाया गया है.

• टोमोटाका टाकाहाशी, कार निर्माता टोयोटा और विज्ञापन कंपनी डेन्ट्सू ने संयुक्त रूप से रोबोट किरोबो व उसका साथी मिराटा बनाया है.

• यह दोनों रोबोट मनुष्य से बातचीत कर सकते हैं. इन दोनों रोबोट में आवाज पहचानने की क्षमता, चेहरा पहचाने की क्षमता है. इनमें कैमरा, मनुष्य के भाव कैद करने वाला सॉफ्टवेयर, बोलने के लिए यंत्र आदि लगे हैं.

भारत का उपग्रह इनसेट -3डी पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित

भारत का मौसम संबंधी उन्नत उपग्रह, इनसेट-3डी सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में 1 अगस्त 2013 को स्थापित हुआ. उपग्रह इनसेट-3 डी का फ्रेंच गयाना (फ्रेंच गयाना दक्षिणी अमेरिका के उत्तर अटलांटिक तट पर फ्रांस का एक विदेशी क्षेत्र है.) स्थित कौरु से सफल प्रक्षेपण 26 जुलाई 2013 को किया था. इनसेट-3डी इस समय 82 पूर्व देशांतर स्थित अपने अंतिम भू-स्थैतिक कक्षा की ओर बढ़ रहा है और इसके द्वारा 6

अगस्त 2013 को अपने निर्दिष्ट स्थल पर पहुंच जाना है. बाद में मौसम विज्ञान संबंधी दो पे-लोड और दो ट्रांसपोंडर 8 अगस्त 2013 तक सक्रिय किए जाने हैं. उसके बाद मौसम संबंधी आंकड़े प्राप्त होने शुरू हो जाने हैं. यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के रॉकेट एरियन-5 ने इनसेट-3 डी और एल्फासेट उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े थे. हिन्द महासागर के ऊपर भूस्थिर कक्षा में यह पहला साउंडर सिस्टम है. स्वदेश में विकसित इनसेट-3डी के मौसम संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के नई दिल्ली केंद्र में एक तंत्र विकसित किया.

उपग्रह इनसेट-3 डी

• इनसेट-3 डी द्वारा वातावरण में सतह से शिखर तक तापमान और नमी तथा ओजोन की मात्रा का पूरा विवरण देते हुए मौसम की निगरानी की जानी है.

• इनसेट-3 डी में नया 19 चैनल का साउंडर लगा है, जिसे इसरो ने किसी उपग्रह में पहली बार भेजा है.

• इनसेट 3 डी का वजन 2060 किलो है.

• इस पर इमेजर, साउंडर, डाटा रिलो ट्रांसपोंडर और सैटेलाइट एडेड सर्च एंड रेस्क्यू जैसे चार पेलोड लगे हुए हैं.

• इस पर लगा 6 चैनल वाला इमेजर पृथ्वी के मौसम संबंधी चित्र ले सकता है.

• इनसेट-3डी पर लगा तीसरा पैलोड डाटा रिले ट्रांसपोंडर द्वारा मौसम विज्ञान, जल विज्ञान और समुद्र विज्ञान संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराए जाने हैं. इससे मौसम संबंधी सटीक भविष्यवाणियां की जा सकेंगी.

न्यूज़ कैप्सूल

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कार्यक्रम अहिंसा संदेशवाहक का शुभारंभ

यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केन्द्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्रालय के कार्यक्रम 'अहिंसा संदेशवाहक' (अहिंसा मैसेन्जर्स) का शुभारंभ नई दिल्ली में 31 अगस्त 2013 को किया.

अहिंसा मैसेन्जर्स कार्यक्रम का उद्देश्य

राष्ट्रीय खेल दिवस

राष्ट्रीय खेल दिवस को हॉकी के पूर्व खिलाड़ी मेजर ध्यान चंद के जयंती पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है. राष्ट्रीय खेल दिवस के आयोजन खेलों को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है. राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर नई दिल्ली के मेजर ध्यान चंद स्टेडियम में सद्भावना हॉकी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है. मेजर ध्यान चंद को 'हॉकी का जादूगर' भी कहा जाता है.

दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को पहला महाथीर शांति पुरस्कार दिया गया

पहले महाथीर शांति पुरस्कार (Mahathir Award for Global Peace) के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को 'महाथीर शांति पुरस्कारः लाइफटाइम कैंपेनर फॉर पीस एण्ड फ्रीडम' (Mahathir Award for Global Peace: Lifetime Campaigner for Peace and Freedom) से 27 अगस्त 2013 को पुरस्कृत किया गया. दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान राष्ट्रपति जैकब जुमा ने मंडेला की ओर से पुरस्कार ग्रहण किया. नेल्सन मंडेला प्रिटोरिया के अस्पताल में कठिन अवस्था में भर्ती हैं. मलेशिया के पुत्रजया स्थित पुत्रजया अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में मलेशिया के भूतपूर्व प्रधानमंत्री तुन डॉक्टर महाथीर बिन मोहम्मद ने दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान राष्ट्रपति जैकब जुमा को नेल्सन मंडेला के लिए पुरस्कार दिया. साथ ही, 'महाथीर शांति पुरस्कारः लाइफटाइम कैंपेनर फॉर ग्लोबल पीस' (Mahathir Award for Global Peace: Lifetime Campaigner for Global Peace) का पुरस्कार मलेशिया के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर महाथीर बिन मोहम्मद को दिया गया.

महाथीर ग्लोबल पीस फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी तथा अध्यक्ष, लिम लोक विंग के द्वारा आरंभ किया गया और इसे शांति के काम करने; उस विश्व की रचना करने व उसे बनाये रखने के लिए जिसमें हम रहना चाहते हैं; और उस शांतिपूर्ण विश्व की रचना करने, जिसे हम आने वाली पीढ़ियों को विरासत में देना चाहते हैं; के लिए दिया जाना है. महाथीर शांति पुरस्कार तथा महाथीर ग्लोबल पीस फाउंडेशन दोनो का ही नाम मलेशिया के भूतपूर्व प्रधानमंत्री महाथीर बिन मोहम्मद के नाम पर रखा गया है. महाथीर बिन मोहम्मद मलेशिया के एक राजनीतिज्ञ हैं और वे मलेशिया के चौथे प्रधानमंत्री रह चुके हैं. महाथीर अपने पद पर 1981 से लेकर 2003 तक (22 वर्षों तक) बने रहे.

केएन बाशा ने बौद्धिक संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया

मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) केएन बाशा ने बौद्धिक संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद का कार्यभार 28 अगस्त 2013 को ग्रहण किया.

केएन बाशा

• 10 दिसंबर 2005 को उन्हें मद्रास उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया और वह 13 मई 2013 तक इस पद पर रहे.

• उन्होंने वर्ष 1976 में अधिवक्ता के रूप में कार्य करना शुरू किया.

• वर्ष 1985 में उन्होंने एक दीवानी और फौजदारी अधिवक्ता के रूप में स्वतंत्र अभ्यास शुरू किया.

• उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई की और मद्रास लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री प्राप्त की.

• न्यायमूर्ति केएन बाशा का जन्म मई 1951 में हुआ था.

बौद्धिक संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण (आईपीएटी)

बौद्धिक संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण (आईपीएटी) की स्थापना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में केंद्र सरकार द्वारा 15 सितंबर 2003 में की गई. इसका कार्य ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 और सामान भौगोलिक संकेत (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत दिए गए निर्णयों के खिलाफ अपील की सुनवाई करना है. बौद्धिक संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में है और इसकी अन्य पीठें चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद में स्थित हैं.

पूर्व राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार डीसी प्रशांत का जम्मू-कश्मीर में निधन

पूर्व राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार डीसी प्रशांत का जम्मू-कश्मीर में उनके निवास पर 28 अगस्त 2013 को निधन हो गया. वह 96 वर्ष के थे और काफी समय से बीमार थे.

डीसी प्रशांत के जीवन से संबंधित मुख्य तथ्य

• वह जम्मू-कश्मीर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुने जाने के बाद 1982 से 1988 तक राज्यसभा के सदस्य रहे.

• पत्रकारिता और डोगरी तथा हिन्दी भाषा के क्षेत्र में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान किया.

• वह डोगरी संस्था के संस्थापक सदस्य थे और उन्होंने डोगरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज कराने हेतु अथक संघर्ष किया.

• डोगरी भाषा के आठवीं अनुसूची में शामिल होने के बाद उन्होंने स्नातकोत्तर स्तर तक शैक्षणिक संस्थानों में डोगरी भाषा लागू किए जाने का अभियान चलाया.

• वह आकाशवाणी और पीटीआई से भी लम्बे समय तक जुड़े रहे.

• हिन्दी और डोगरी में डीसी प्रशांत के नाटकों ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दी.

• डीसी प्रशांत ने अपना करियर आजादी से पहले असोसिएटेड प्रेस से शुरू किया था.

• उनके परिवार में तीन बेटे और चार बेटियां हैं.

इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस पीस प्राइज 2013 हेतु मलाला यूसुफजई का चयन

पाकिस्तानी किशोरी मलाला यूसुफजई को इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस पीस प्राइज-2013 (International Children's Peace Prize 2013) से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया. पुरस्कार आयोजकों ने इसकी घोषणा 27 अगस्त 2013 को की. मलाला यूसुफजई को यह पुरस्कार पाकिस्तान में तालिबान के फरमान को चुनौती देते हुए लड़कियों की शिक्षा की जोरदार पैरोकारी करने के लिए प्रदान किया जाएगा. पुरस्कार आयोजकों ने अपने बयान में कहा 16 वर्षीय मलाला को 6 सितंबर 2013 को 'द हेग' (नीदरलैंड) में एक कार्यक्रम के दौरान इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस पीस प्राइज से सम्मानित किया जाएगा. मलाला बहुत बहादुर और प्रतिभाशाली हैं. मलाला यूसुफजई को यह सम्मान यमन मूल के वर्ष 2011 के नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता त्वाकोल कारमान के द्वारा प्रदान किया जाना है.

इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस पीस प्राइज

इस पुरस्कार का प्रारम्भ वर्ष 2005 में सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्वाचोव ने उस समय की जा वह रोम में नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेताओं की समिति की अध्यक्षता कर रहे थे. यह पुरस्कार डच किड्स राइट्स फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है. किड्स राइट्स फाउंडेशन नीदरलैंड की राजधानी एम्सटर्डम में स्थित है. पुरस्कार के तहत विजेता को एक लाख यूरो (133000 यूएस डालर) की नगद राशि प्रदान की जाती है.

विदित हो कि क्रिस केज वाल्डेज को 2012 का इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस पीस प्राइज प्रदान किया गया था.

मुद्रा विनिमय के माध्यम से विदेशी व्यापार की संभावनाओं की तलाश हेतु समिति का गठन

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 27 अगस्त 2013 को मुद्रा विनिमय (करेंसी स्वैपिंग, Currency Swapping) के माध्यम से विदेशी व्यापार की संभावनाओं का पता लगाने हेतु एक समिति का गठन किया. इस समिति का गठन विदेशी व्यापार में लगातार बढ़ते घाटे एवं विदेशी मुद्राओं विशेषकर डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमत को रोकने के लिए मुद्रा विनिमय जैसे विकल्पों के प्रयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए किया गया है. इस समिति को चार सप्ताह में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है. विदेशी व्यापार को मुद्रा विनिमय के माध्यम से करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए गठित

इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1988 में भारत के उद्योगपति स्वर्गीय राय बहादुर गूजरमल मोदी के स्मृति में किया गया था. यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है. गूजरमल मोदी नवप्रवर्तनकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिक पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है. इस पुरस्कार के तहत विजेता को दो लाख एक हजार रुपये नकद, प्रशस्ति पत्र तथा चांदी की एक शील्ड प्रदान किया जाता है. यह पुरस्कार गूजर मल मोदी साइंस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है.

विदित हो कि वर्ष 2012 का गूजरमल मोदी नवप्रवर्तनकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिक पुरस्कार वैज्ञानिक केएस वल्दिया और प्रो. एके सूद को प्रदान किया गया.

खेल | खिलाड़ी

साइना नेहवाल के नेतृत्व वाली हैदराबाद हॉटशॉट्स ने आइबीएल के प्रथम संस्करण का खिताब जीता

भारत की शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के नेतृत्व वाले हैदराबाद हॉटशॉट्स ने इंडियन बैडमिंटन लीग (आइबीएल) के पहले संस्करण का खिताब जीत लिया. हैदराबाद हॉटशॉट्स की टीम ने पीवी सिंधु के नेतृत्व वाली अवध वॉरियर्स टीम को 3-1 से हराया. फाइनल मैच मुंबई के सरदार पटेल स्टेडियम में 31 अगस्त 2013 को खेला गया था. इंडियन बैडमिंटन लीग (आइबीएल) की इनामी राशि दस लाख डॉलर (लगभग छह करोड़ रुपये) है. टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला नहीं गंवाने वालीं साइना नेहवाल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया. इसके तहत उन्हें 1000 डॉलर की इनामी राशि दी गई. टूर्नामेंट की विजेता टीम हैदराबाद हॉटशॉट्स को इनाम में तीन करोड़ 25 लाख रुपये मिले, जबकि उपविजेता अवध वॉरियर्स की टीम को एक करोड़ 75 लाख रुपये मिले. इस फाइनल मैच के दौरान विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में साइना नेहवाल को चौथा जबकि पीवी सिंधु को 10वां स्थान प्राप्त था. पहले सेमीफाइनल में हैदराबाद हाटशाट्स ने महाराष्ट्र की अन्य टीम पुणे पिस्टंस को 3-0 से जबकि दूसरे सेमीफाइनल में अवध वॉरियर्स टीम ने मुंबई मास्टर्स को 3-2 से हराया था.

बायर्न म्युनिख के मिडफील्डर फ्रांक रिबेरी ने यूईएफए बेस्ट प्लेयर इन यूरोप अवार्ड जीता

चैंपियंस लीग की विजेता टीम बायर्न म्युनिख के मिडफील्डर फ्रांक रिबेरी ने वर्ष 2012-13 के लिए यूईएफए बेस्ट प्लेयर इन यूरोप अवार्ड 29 अगस्त 2013 को जीता. यह यूरोपीय फुटबॉल का सबसे

कार्पोरेट

एचएलएल बायोटेक लिमिटेड का क्रोएशिया के इंस्टीट्यूट ऑफ इम्युनोलॉजी के साथ समझौता

एचएलएल बायोटेक लिमिटेड ने भारत में खसरा वैक्सिन के बड़े पैमाने के उत्पादन हेतु क्रोएशिया में जगरेब, के इंस्टीट्यूट ऑफ इम्युनोलॉजी के साथ लंबी अवधि का आपूर्ति और तकनीकी हस्तांतरण समझौता किया. तिरूवनंतपुरम में एचएलएललाईफ केयर लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर एम अयप्पन ने बताया कि कंपनी द्वारा भारतीय बाजार हेतु खसरा वैक्सिन की 8 करोड़ खुराकें तैयार की जानी है. इससे वैक्सिन की मौजूदा मांग काफी हद तक पूरी की जा सकेगी.

समझौते का उद्देश्य

• यह समझौता भारत में खसरा वैक्सिन के बड़े पैमाने के उत्पादन के लिए किया गया.

• समझौते से वैक्सिन की अगली उन्नत किस्म के विकास में मदद प्राप्त होनी है.

एचएलएल बायोटेक लिमिटेड

एचएलएल बायोटेक लिमिटेड केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की मिनीरत्न कंपनी एचएलएललाईफ केयर लिमिटेड की सहायक कंपनी है. एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एचबीएल) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम और अन्य नई पीढ़ी के टीके के उत्पादन के लिए एक प्रीमियम की सुविधा

स्थापित करने के लिए भारत सरकार की साझेदारी है. एचबीएल दक्षिण भारत में चेन्नई के निकट चेंगलपट्टू (तमिलनाडु) में स्थित है. एचबीएल का मुख्य उद्देश्य सस्ती कीमत पर सुरक्षित और प्रभावी टीके सुनिश्चित करना है.

डीके सराफ ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) के अध्यक्ष नियुक्त

डीके सराफ को ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) का अध्यक्ष 30 अगस्त 2013 को नियुक्त किया गया. डीके सराफ द्वारा सुधीर वासुदेव का स्थान लिया जाना है. सुधीर वासुदेव 28 फरवरी 2014 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. इस नियुक्त से पूर्व डीके सराफ ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पद पर रहे.

इस पद हेतु हुए साक्षात्कार के आधार पर पीईएसबी बोर्ड (लोक उद्यम चयन बोर्ड) ने इस पद के लिए डीके सराफ के नाम की सिफारिश की. ओएनजीसी के अध्यक्ष पद के लिए गेल इंडिया में वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बीसी त्रिपाठी के नाम की भी सिफारिश की गई थी. लेकिन वह साक्षात्कार के लिए उपस्थित नहीं हुए. तेल एंव गैस क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी होने के नाते ओएनजीसी के अध्यक्ष का पद काफी महत्वपूर्ण माना जाता है.

लोक उद्यम चयन बोर्ड (Public Enterprises Selection Board)

लोक उद्यम चयन बोर्ड भारत सरकार द्वारा गठित एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय है. लोक उद्यम चयन बोर्ड केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए एक स्वस्थ प्रबंधकीय नीति विकसित करने के लिए खासकर, उच्च प्रबंधन पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने के लिए स्थापित किया गया.

ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी)

ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) 23 जून 1993 से प्रारंभ हुई एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी है. यह भारत मे कच्चे तेल के कुल उत्पादन मे 77 प्रतिशत और गैस के उत्पादन मे 81 प्रतिशत का योगदान करती है. यह सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाली कंपनी है. इसे 14 अगस्त 1956 को एक आयोग के रूप में स्थापित किया गया था. इस कंपनी में भारत सरकार की कुल इक्विटी हिस्सेदारी 74.14 प्रतिशत है. ओएनजीसी कच्चे तेल के अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों में संलिप्त है. यह भारत के कच्चे तेल की कुल आवश्यकता का लगभग 30 प्रतिशत उत्पादन करती है. इसके स्वामित्व मे एक 11000 किलोमीटर लम्बी पाइपलाइन है जिसका परिचालन यह स्वंय करती है.

वीडियोकॉन मोबाइल सर्विसेज की वर्ष 2014 में 4जी सेवाएं शुरू करने की योजना

राज्य

मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2013 के सर्वोच्च खेल पुरस्कार प्रदान किए

मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2013 के सर्वोच्च खेल पुरस्कार 28 अगस्त 2013 को एक समारोह में प्रदान किए. इस बार मलखम्भ में एक नया पुरस्कार 'प्रभाष जोशी अवार्ड' दिया गया. मध्यप्रदेश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार विक्रम, एकलव्य, विश्वामित्र तथा लाइफ टाइम अचीवमेंट खेल पुरस्कार 2013 हेतु चयनित खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के नामों की घोषणा 22 अगस्त 2013 को की गई थी. मध्य प्रदेश में प्रत्येक वर्ष खेल दिवस (29 अगस्त) के अवसर पर खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं. इस समारोह में इस बार अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी एमसी मैरीकॉम विशेष अतिथि रहीं. समारोह में एमसी मैरीकॉम को लंदन ओलंपिक-2013 में बॉक्सिंग का कांस्य पदक जीतने पर प्रदेश सरकार द्वारा 50 लाख की सम्मान राशि से सम्मानित किया गया. उन्हें 29 अगस्त 2013 को दिल्ली में अवार्ड समारोह में उपस्थित रहना है, इसलिए इस बार पुरस्कार समारोह एक दिन पहले आयोजित किया गया.

राज्य में खेल जगत में उत्कृष्ट योगदान देने वाले खिलाड़ियों को निम्नलिखित चार सम्मान दिए जाते हैं:

• **विक्रम पुरस्कार:** 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है.

• **एकलव्य पुरस्कार:** उदीयमान खिलाड़ियों को दिया जाता है. विक्रम पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी भी दी जाती है.

• **विश्वामित्र पुरस्कार:** प्रशिक्षकों को दिया जाता है.

• **लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार:** जीवन पर्यन्त खेल की सेवा करने के लिए दिया जाता है.

चयनित खिलाड़ियों की सूची

विक्रम पुरस्कार- 2013: दिलीप सिंह नेगी भोपाल (कयाकिंग-केनोइंग), अंकित सोनकर जबलपुर (कराते), आरती खकाल इंदौर (ताईक्वांडो), शनु महाजन भोपाल (फेन्सिंग), सुरभि पाठक इंदौर (शूटिंग), रोहन सिंह ठार जबलपुर (वूशु), जलज सहाय सक्सेना इंदौर (क्रिकेट), अंजली ठार भोपाल (साफ्ट टेनिस), कामिल कय्यूम खान भोपाल (कयाकिंग-केनोइंग).

एकलव्य पुरस्कार- 2013: गणेश्वरी धुर्वे डिण्डोरी (कयाकिंग-केनोइंग), वर्षा बर्मन भोपाल (शूटिंग), राघव जय सिंघानी इंदौर (टेनिस), रोहित ईमोलिया इंदौर (तैराकी), भुरया दुबे अशोक नगर (वूशु), आशा रोका भोपाल (बॉक्सिंग), यश सक्सेना ग्वालियर (कराते), शैला क्लेयर चार्ल्स बालाघाट (सेलिंग), यांशी परदेशी इंदौर (बेडमिंटन), यामिनी मौर्य सागर (जूडो), अक्षत भाटी इन्दौर (घुड़सवारी), मो आरिफ अब्बासी इंदौर (बास्केटबॉल), कीर्ति चंदानी भोपाल (साफ्ट टेनिस).

विश्वामित्र पुरस्कार- 2013: भोपाल की कयाकिंग-केनोइंग के प्रशिक्षक मतीएल विश्वेश्वरी देवी, इन्दौर के शूटिंग प्रशिक्षक मुराद खाँ तथा इन्दौर के ही कबड्डी के प्रशिक्षक रामचन्द्र पाण्डेय को इस वर्ष का विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया.

लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार-2013: यह पुरस्कार वालीबाल के रामलाल वर्मा को खेल की जीवन पर्यन्त उल्लेखनीय सेवा हेतु दिया गया.

प्रभाष जोशी पुरस्कार-2013: पहली बार दिया जाने वाला प्रभाष जोशी अवार्ड अजय वक्तारिया को मलखम्ब खेल में लगातार सतत रूप से अर्जित की गई उपलब्धियों को देखते हुए दिया गया.

असम सरकार ने असम राज्य नागरिक आपूर्ति निगम बनाने का निर्णय किया

असम सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बेहतर प्रबंधन के लिए असम राज्य नागरिक आपूर्ति निगम बनाने का निर्णय 27 अगस्त 2013 को किया. प्रस्तावित निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली